एच-1बी पर 98 लाख लगेगी फीस

नए बीजा प्रस्ताव के बाद अमेरिका में भारतीयों को नौकरी नहीं होगी आसान

वॉशिंगटन, 24 अगस्त, एजेंसी. अमेरिका में नौकरी करने का सपना देख रहे विदेशी हाई-स्किल प्रोफेशनल्स के लिए एच-1बी बीजा से जुड़ा नया प्रस्ताव चर्चा में है. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने वीजा पर 1,03,265 डॉलर यानी करीब 98 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव जारी किया है.

एच-1बी बीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशों से विशेष कौशल वाले कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नियुक्त करने की अनुमति देता है. प्रस्ताव लागू

होने पर मौजूदा आवेदन लागत की तुलना में कंपनियों पर बड़ा अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है. मौजूदा व्यवस्था में एच-1बी आवेदन के लिए कंपनियों को लगभग 2,000 से 5,000 डॉलर तक शुल्क देना पड़ता है. प्रस्तावित रकम इससे कई गुना अधिक है. नया नियम इस साल के अंत तक लागू हो सकता है. इस प्रस्ताव का भारतीय युवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है. एच-1बी कार्यक्रम का इस्तेमाल भारतीय आईटी और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स बड़े पैमाने पर करते हैं. हालांकि, प्रस्ताव लागू होने और इसकी अंतिम शर्तों को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी.

यूएस में भारतीय मूल की आबादी

वर्ष	भारतीय
2026 करीब	55 लाख
2025	54 लाख
2024	52 लाख

पहले भी विवादों में रही है भारी फीस

पिछले साल ट्रम्प प्रशासन ने एक अस्थायी आदेश के जरिए ऐसी फीस लागू की थी. जून में अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने इसे गैरकानूनी करार देते हुए सरकार को शुल्क वसूलने से रोक दिया था. मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. बोस्टन की अपीलीय अदालत फैसले की समीक्षा कर रही है, जबकि वॉशिंगटन डीसी की एक अन्य अदालत में कारोबारी संगठन की याचिका पर सुनवाई से जुड़ी प्रक्रिया जारी है.

बंगाल में बड़े झटके के बाद ममता ने स्पष्ट कर दिया भविष्य का राजनीतिक प्लान

संन्यास नहीं लूंगी, भाजपा से लड़ूंगी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

कोलकाता, 25 अगस्त. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से पीछे धकेलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

ममता बनर्जी ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर लाइव संबोधन के दौरान की. उनका बयान ऐसे समय आया है, जब तृणमूल कांग्रेस के भीतर

बगावत और संगठनात्मक खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं. ममता ने कहा कि केवल बैठक की अनुमति नहीं मिलने के कारण उनके राजनीति से हटने की उम्मीद करने वाले लोग गलतफहमी में हैं.

टीएमसी बागियों पर कसा शिकंजा

तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय से जुड़ा विवाद अब न्यायिक स्तर पर पहुंच गया है. अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सांसदों और लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया है. याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित अयोग्यता संबंधी अर्जियों पर कार्रवाई की मांग की गई है.

बागी विधायक कासिम सिद्दीकी की घर वापसी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान के बीच अमदंगा से विधायक कासिम सिद्दीकी ने फिर पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े होने का ऐलान किया है. कुछ महीने पहले तृणमूल से अलग रुख अपनाकर विपक्षी नेता ऋत्राव्रता बनर्जी के गुट में शामिल हुए सिद्दीकी ने अब उस समूह से दूरी बना ली है.

हिम्मत है तो गुजरात के स्कूल दिखाओ

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 25 अगस्त. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे दावों पर पलटवार किया है. उन्होंने भाजपा को गुजरात और पंजाब के एक-एक हजार सरकारी स्कूलों का संयुक्त निरीक्षण कराने की चुनौती दी.

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा गुजरात के 1000 स्कूलों की सूची दे और आम आदमी पार्टी पंजाब के 1000 विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराए. इसके बाद दोनों राज्यों के संस्थानों की स्थिति का मिलकर जायजा लिया जाए. वीडियो संदेश में केजरीवाल ने

आप प्रमुख केजरीवाल ने बीजेपी को दी खुली चुनौती

भाजपा पंजाब की पुरानी तस्वीरों से कर रही बदनाम

पंजाब में 19000 सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर

आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब के सरकारी स्कूलों को बदनाम करने के लिए पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने दावा किया कि जिस विद्यालय का वीडियो भाजपा की ओर से साझा किया जा रहा है, वह वर्ष 2018 का है. उनके मुताबिक उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी. केजरीवाल ने कहा कि गलतियों की ओर ध्यान दिलाया जाए तो उन्हें सुधारने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन गलत या पुराने वीडियो के जरिये राज्य की छवि खराब नहीं की जानी चाहिए. आप नेता ने कहा कि गुजरात में लंबे समय से भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को करीब साढ़े चार वर्ष हुए हैं. इसी आधार पर उन्होंने दोनों राज्यों के विद्यालयों की स्थिति की प्रत्यक्ष तुलना करने का प्रस्ताव रखा.

स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलेगी : कोर्ट

छात्रा की याचिका खारिज

प्रयागराज, 25 नवभारत न्यूज अगस्त. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल में तय ड्रेस के साथ स्कार्फ अथवा हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी है.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि विद्यालय की निर्धारित वर्दी विद्यार्थियों में समानता, अनुशासन और संस्थागत पहचान को मजबूत करती है. अदालत ने माना कि एक समान ड्रेस व्यवस्था सभी समुदायों के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होती है और इससे धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है. मामला प्रयागराज के अत्तरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी से जुड़ा है. छात्रा ने हाईस्कूल की पढ़ाई इसी संस्थान से पूरी की थी और कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहती थी. उसका कहना था कि वह कक्षा छह से स्कार्फ पहनकर विद्यालय आती रही है और उस दौरान स्कूल प्रबंधन ने कोई आपत्ति नहीं जताई.

वांगचुक फिर आंदोलन की राह पर

लद्दाख हिंसा की बरसी पर एक माह तक स्वतंत्र राज्य के लिए प्रदर्शन का ऐलान

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 25 अगस्त. लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा की बरसी से पहले आंदोलन का मुद्दा फिर गरमा गया है. लेह में आयोजित कैंडल मार्च में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने पिछले साल जान गंवाने वाले लोगों को याद किया और कहा कि अगले एक माह तक उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ न्याय और जवाबदेही की मांग उठाई जाएगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि शुरुआती कार्यक्रम प्रतीकात्मक है, जबकि आगे व्यापक और

शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जाएंगे. वांगचुक के मुताबिक, लद्दाख के लोग पिछले कई वर्षों से राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने, रोजगार की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र के सामने अपनी मांग रखते रहे हैं. उनका कहना है कि बातचीत में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण लोगों में असंतोष बढ़ा है.

जांच पर भी उठाए सवाल

उन्होंने 24 सितंबर 2025 की घटना की न्यायिक जांच को लेकर भी सवाल उठाया. केंद्र सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया था. आयोग को हिंसा की परिस्थितियों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और हुई मौतों की जांच करनी है. लद्दाख प्रशासन के अनुसार आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं और सार्वजनिक हलफनामे भी प्राप्त किए हैं. हालांकि, अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है. मई 2026 में केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी.

एक नजर में

योगी 1 लाख युवाओं को देंगे नौकरी

लखनऊ, 25 अगस्त (नवभारत न्यूज). उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को सरकारी रोजगार देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में प्रदेश के एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. इसके लिए अलग-अलग चरणों में हर सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री के मुताबिक संबंधित भर्ती परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और अब परिणाम जारी करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने आयोगों और भर्ती बोर्डों से परिणाम की समयसीमा और कम करने को कहा है.

ईरान ने फिर पेश की मोजतबा की मौजूदगी

तेहरान, 25 अगस्त. ईरान में सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सेहत और सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक नया वीडियो सामने आया है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, फुटेज में मोजतबा एक धार्मिक अकादमिक अध्ययन सत्र की अध्यक्षता करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सार्वजनिक किया. हालांकि, रिकॉर्डिंग कब की है, इसकी कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई गई है. यह दृश्य उस समय का है जब मोजतबा देश के सर्वोच्च नेता नहीं बने थे. फुटेज में वह कुछ लोगों के बीच बैठे नजर आते हैं. चर्चा शुरू होने से पहले मौजूद लोग प्रार्थना करते दिखाई देते हैं. इसके बाद मोजतबा छात्रों को इस्लामिक सिक्योरिटी मॉडल विषय पर संबोधित करते सुनाई देते हैं.

पाकिस्तान की सरहद यूनिवर्सिटी में बवाल

इस्लामाबाद, 25 अगस्त. सरहद यूनिवर्सिटी के रावत कैंपस में 24 अगस्त को छात्रों का एक समूह फीस और कक्षा समय को लेकर विभागीय प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्टूडेंट अफेयर्स की प्रमुख डॉ. आइना विद्यार्थियों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचीं. कुछ छात्रों के पीछे नहीं हटने पर उन्होंने अपने पति को परिसर में बुलाया, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी बताए जा रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, सैन्य अधिकारी वर्दी में परिसर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित तौर पर मारपीट की. इसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और हवा में गोली चलाई.

फॉक्सवैगन में 1 लाख नौकरियों पर संकट

वोल्फसबर्ग, 25 अगस्त. जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन में लागत घटाने और कारोबार का आकार कम करने की प्रस्तावित योजना को लेकर कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ गया है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवर ब्लूम वोल्फसबर्ग स्थित कंपनी की प्रमुख फैक्ट्री में कर्मचारियों के सामने बदलावों की रूपरेखा रखेंगे. प्रस्तावित कदमों से करीब एक लाख कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़ सकता है. इसके बाद जर्मनी के अन्य संयंत्रों में भी कर्मचारियों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं. फॉक्सवैगन इस समय कई कारोबारी चुनौतियों से गुजर रही है.

बढ़े दामों के बाद चीनी की जमाखोरी पर सरकार सख्त

- **आयातित चीनी 60 दिन में बाजार में उतारनी होगी**
- **31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी आयात की अनुमति**

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 25 अगस्त. चीनी की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने आयातित चीनी को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं.

टैरिफ रेट कोटा के तहत आने वाली कच्ची चीनी को अब देश में पहुंचने की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिफाइंड कर बाजार में बेचना अनिवार्य होगा. सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन चीनी आयात की अनुमति दी है. इस कदम का उद्देश्य आयातित माल को लंबे समय तक गोदामों में रखने और संभावित जमाखोरी पर रोक लगाना है. नए प्रावधानों के मुताबिक बिल ऑफ एंट्री की तारीख से दो महीने के भीतर कच्ची चीनी की प्रोसेसिंग पूरी करनी होगी और तैयार उत्पाद को घरेलू बाजार में उतारना होगा. पहले आयातित कच्ची चीनी को प्रोसेस कर 31 अक्टूबर तक बाजार में उपलब्ध कराने की शर्त थी. अब प्रत्येक खेप के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की गई है. सरकार ने केवल आयात की समयसीमा ही नहीं बदली है, बल्कि घरेलू बाजार में उपलब्ध स्टॉक की निगरानी भी बढ़ाई है.

असम में 9000 करोड़ का सुपर हाईवे

135 किमी का नया हाईवे बदलेगा कनेक्टिविटी का नक्शा

नवभारत न्यूज नेटवर्क

गुवाहाटी, 25 अगस्त. असम में प्रस्तावित गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर को पूर्वोत्तर की परिवहन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है. 135.87 किलोमीटर लंबा यह मार्ग बैहाटा चारियाली से शुरू होकर तेजपुर तक जाएगा.

परियोजना को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किया जाएगा. इसके निर्माण पर करीब 9,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. नए मार्ग से गुवाहाटी और तेजपुर के बीच आवागमन अधिक तेज होने की उम्मीद है. परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय में करीब आधी तक कमी आ सकती है. कॉरिडोर में कुल 58.7 किलोमीटर लंबे पांच बाईपास प्रस्तावित हैं. ये बैहाटा चारियाली, सिपाझार, खारूपेटिया, डेकियाजुली और तेजपुर में बनाए जाएंगे. इनका उद्देश्य आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले यातायात को अलग मार्ग देना और स्थानीय सड़कों पर दबाव कम करना है. प्रस्तावित ढांचे में एक हाथी अंडरपास, 15 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर और करीब 210 किलोमीटर सर्विस रोड शामिल हैं. हाथी अंडरपास का उद्देश्य वन्यजीवों की आवाजाही के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना है.

आज का इतिहास

1609: वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने वेनिस के शासकों के सामने पहली शक्तिशाली दूरबीन का प्रदर्शन किया था.

1825: उरुग्वे ने ब्राजील के साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी.

1944: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चार साल के नाजी कब्जे के बाद पेरिस शहर को आजाद कराया गया.

1957: भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता था.

अमेजन, स्विगी के लाइसेंस सस्पेंड

बेंगलुरु. कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ऑनलाइन मंचों पर जहरीले धतूरे के फल और बीजों की खाद्य पदार्थ के रूप में बिक्री पाए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने अमेजन, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिगबास्केटके खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित करने का आदेश दिया है. साथ ही तीनों मंचों को इंसानों के सेवन के लिए धतूरे से जुड़ी सभी सूची, विज्ञापन और प्रचार सामग्री तत्काल हटाने तथा इसकी खाद्य वस्तु के रूप में बिक्री और वितरण रोकने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की शुरुआत स्विगी इंस्टामार्ट के जरिये भेजे गए धतूरे के फलों के एक पैकेट को लेकर ग्राहक की शिकायत से हुई.

राहुल ने जनगणना पर साधा निशाना

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 25 अगस्त. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना-2027 में जातिगत आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.

दोनों नेताओं ने कहा है कि जातियों के नाम दर्ज करने के लिए केवल खुला विकल्प रखने से एक ही समुदाय अलग-अलग नामों या उपजातियों के रूप में दर्ज हो सकता है. इससे वास्तविक संख्या का आकलन और विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों की तुलना कठिन होने की आशंका है. पत्र में कांग्रेस नेताओं ने प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों

जाति में विकल्प से फैलेगा भ्रम

और आम लोगों से सलाह लेने की मांग की है. उन्होंने विशेष रूप से जनगणना के सवालों में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर आपत्ति जताई. उनका कहना है कि इससे ओबीसी आबादी से जुड़े आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से जुटाने में समस्या पैदा हो सकती है. राहुल गांधी और खड़गे ने जातियों की पहचान के लिए एक समान व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है. इसके लिए सरकारी जाति सूचियों और भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण से संबंधित सूची का उपयोग करने तथा तय विकल्प या ड्रॉप-डाउन व्यवस्था देने की मांग की गई है. उन्होंने बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई प्रक्रियाओं का उदाहरण भी दिया है. केंद्र की ओर से 14 अगस्त को जनगणना-2027 में पूछे जाने वाले 40 सवालों की सूची जारी की गई थी. इसमें पहली बार आजादी के बाद सभी समुदायों की जातिगत जानकारी दर्ज करने का प्रावधान बताया गया है. जाति संबंधी प्रश्न सूची में 10वें स्थान पर है और इसमें एससी, एसटी के साथ जाति का विकल्प भी शामिल किया गया है.

पंजाब में अकेले उतरेगी बसपा

मायावती ने गठबंधन पर साफ किया रुख

नवभारत न्यूज

लखनऊ/चंडीगढ़, 25 अगस्त. पंजाब की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं. बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में किसी भी दल के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है.

पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय में पंजाब के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि बसपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह पंजाब में भी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी के

अनुसार, पहले किए गए गठबंधनों से उसे अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिला और सीटों के साथ मत प्रतिशत पर भी प्रतिकूल असर पड़ा. मायावती ने संगठन को मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में सक्रिय करने पर जोर दिया. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी की गई.

हस्तियों के ट्वीट

प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी, लेखक और पॉडकास्टर राज शमानी ने मानसिक आराम और काम के बीच संतुलन को लेकर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक महत्वपूर्ण बात साझा की है. उन्होंने कहा कि काम से ब्रेक लेने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कंप्यूटर या काम की स्क्रीन छोड़कर फोन की स्क्रीन पर समय बिताने लगे. राज शमानी ने लिखा कि जब हम काम के दौरान फोन चलाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या लगातार किसी न किसी तरह की जानकारी ग्रहण करते रहते हैं, तब हमारा दिमाग वास्तव में आराम नहीं कर रहा होता.

अरबपति कारोबारी और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अरुणाचल प्रदेश के इटानगर की टिंकल गोंगो के आत्मविश्वास और जज्बे की जमकर सराहना की है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर टिंकल की कहानी और उनके बेबाक अंदाज को प्रेरणादायक बताया. आनंद महिंद्रा ने लिखा कि अब तक ज्यादातर लोग टिंकल गोंगो का वीडियो देख चुके होंगे और उनकी कहानी से परिचित हो गए होंगे. उन्होंने कहा कि लगभग हर मीडिया संस्थान ने उनकी कहानी को जगह दी है.

बदलाव | **राज्यों के बुजुर्ग नागरिकों समेत राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताएं भी बढ़ीं**

दक्षिणी राज्यों में फर्टिलिटी रेट देश में सबसे कम

नवभारत न्यूज

दिल्ली. 25 अगस्त. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए एक साल का सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने के फैसले ने एक ऐसी बहस को फिर से शुरू किया है, जो एक दशक पहले अजीब लगती थी.

वह यह है कि क्या कुछ भारतीय राज्य अब बहुत ज्यादा बच्चों के बजाय बहुत कम बच्चे होने को लेकर चिंतित हैं? इस बहस को नई धार देता है तथ्यात्मक तर्क कि पूरे दक्षिण भारत में फर्टिलिटी रेट

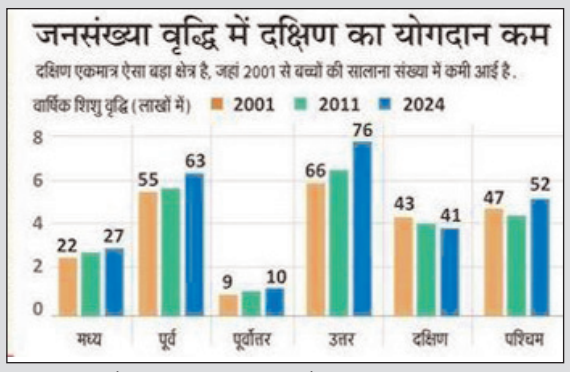

तेजी से गिरे हैं. इससे बढ़ती उम्र की आबादी, भविष्य में श्रम शक्ति की कमी और यहां तक कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं. खासकर जब परिसमन पर केंद्र प्रस्ताव पारित कराने पर दृढ़ है. ऐसे में विजय की यह पॉलिसी दक्षिणी राज्यों में दिख रहे एक बड़े बदलाव का भी हिस्सा है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है, जिसमें तीसरे बच्चे के लिए 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन शामिल है.

राष्ट्रीय दर से भी काफी पीछे दक्षिणी राज्य

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में तमिलनाडु का टोटल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) 1.3 था, जो प्रति महिला 2.1 बच्चों के रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम है. केरल में भी टीएफआर 1.3 दर्ज किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश में यह 1.4, कर्नाटक में 1.5 और तेलंगाना में 1.5 था. उत्तरी और मध्य भारत के साथ अंतर अभी भी काफी है. बिहार ने प्रमुख राज्यों में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट 2.9 दर्ज किया. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2.6, मध्य प्रदेश में 2.4 और राजस्थान में 2.3 रहा. 2024 में भारत का कुल फर्टिलिटी रेट 1.9 था. यह ट्रेंड कई वर्षों से बना हुआ है. 2020 और 2024 के बीच दक्षिणी राज्यों में फर्टिलिटी रेट लगातार रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे रहे.

सीजेपी ने संगठन में किए बड़े बदलाव

नई दिल्ली. सीजेपी ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा की है. पार्टी ने सुधीर सांगवान और सिद्धांत भारद्वाज को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया. दोनों को यह जिम्मेदारी सौरभ दास और आशुतोष रांका के राष्ट्रीय सह-संयोजक बनाए जाने के बाद दी गई है. पार्टी की ओर से संगठन महासचिवों के नामों का भी ऐलान किया गया है. सीजेपी के गठन के बाद शुरुआती दौर में तीन राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की घोषणा की गई थी. इनमें सौरभ दास, आशुतोष रांका और विजेता दहिया शामिल थे. बाद में सौरभ दास और आशुतोष रांका को राष्ट्रीय सह-संयोजक की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रवक्ता के दोनों पद रिक्त हो गए थे.